

राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों को 315753 करोड़ रूपए का गन्ना मूल्य भुगतान

48 लाख किसानों को मिली बड़ी राहत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती —गन्ना आयुक्त

लखनऊ : 12 मार्च, 2026

राज्य सरकार ने गन्ना किसानों की खुशहाली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए अब तक 315753 करोड़ रूपये का गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान सुनिश्चित किया है इससे 48 लाख गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिली है। सरकार की सख्त निगरानी और नियमित समीक्षा के चलते चीनी मिलों द्वारा भुगतान प्रक्रिया में तेजी आई है और वर्तमान पेराई सत्र में 42 चीनी मिलों द्वारा शत-प्रतिशत किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सफलता मिली है। इस गन्ना मूल्य भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरल बनाने के लिए एस्कॉ एकाउन्ट के द्वारा डिजिटल मानिट्रिंग सिस्टम को व्यवहारिक एवं मजबूत बनाया गया है।

यह जानकारी गन्ना आयुक्त श्रीमती मिनिस्ती एस ने देते हुए बताया कि किसानों को गन्ना पर्ची, सर्वे तथा गन्ना मूल्य भुगतान की जानकारी एसएमएस एवं विभागीय पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है। शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य का समय से भुगतान होने से प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों को आर्थिक मजबूती मिली है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए किसान-हितैषी योजनाओं और डिजिटल नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे प्रदेश की भुगतान संबंधी प्रक्रिया में सकारात्मक सफलता मिली है।

गन्ना आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व एवं गन्ना मंत्री श्री लक्ष्मी नाराण चौधरी तथा मा0 राज्यमंत्री श्री संजय सिंह गंगवार के कुशल मार्गदर्शन में गन्ना किसानों के व्यापक हितों को देखते हुए अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग, गन्ना विकास, श्रीमती बीना कुमारी के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश सरकार गन्ना हितैषी नीतियों की प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप गन्ना मूल्य भुगतान के मामलों में ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की गई है। गन्ना आयुक्त ने यह भी बताया कि गन्ना किसानों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा लगातार निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। इन प्रयासों के चलते प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों को रिकार्ड स्तर पर गन्ना मूल्य भुगतान करने में सफलता प्राप्त हुई है।

गन्ना आयुक्त ने बताया कि गन्ना किसान प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है इसलिए उन्हें उनके उत्पाद का उचित और समयबद्ध मूल्य दिलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक गन्ना किसानों को सबसे बड़ी धनराशि का भुगतान करके रिकार्ड बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करते हुए पेराई सत्र 25-26 में गन्ना मूल्य की दरों में 30 रु0 प्रति कु0 की वृद्धि की गयी है। इसके तहत अगैती प्रजातियों के लिए 400 रु0 प्रति कु0 एवं सामान्य प्रजातियों के लिए 390 रु0 प्रति कु0 की दर निर्धारित की गयी है। इस बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने में गन्ना विभाग का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

उल्लेखनीय है कि उन्नत बीज अधिक उत्पादन और समृद्ध किसान के संकल्प को साकार करने के लिए गन्ना खेती में तकनीकी क्रांति को ओर ले जाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। इसके तहत एनएसआई कानपुर और गन्ना शोध परिषद के साथ पिछले महीने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे ब्रीडरशीड की उपलब्धता में 12 हजार कु0 की वृद्धि होगी। और एवं मध्य पूर्वी उ0प्र0 किसानों को फायदा मिलेगा। समझौता ज्ञापन के माध्यम से गन्ना किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने तथा गन्ना खेती को अधिक वैज्ञानिक और लाभकारी बनाने की दिशा में गन्ना विकास विभाग द्वारा नई तकनीक अपनाई जा रही है। गन्ना के नए किस्मों के बीज की उपलब्धता बढ़ाने तथा प्रजातियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी के साथ उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद एवं बलरामपुर चीनी मिल की इकाई हैदरगढ़ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते से टिश्यू कल्चर तकनीकी माध्यम से उन्नत गन्ना प्रजातियों के रोग मुक्त गन्ना पौध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

सम्पर्क सूत्र— केवल

वैशाली माथुर/03:17 PM